

**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com



NEERAJ®

सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification)

B.S.O.E.- 148

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Chhavi Rustogi



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification)

Question Paper—June-2024 (Solved).....	1-2
Question Paper—December-2023 (Solved).....	1-2
Question Paper—June-2023 (Solved).....	1
Question Paper—December-2022 (Solved).....	1
Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved).....	1-2

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	प्रमुख अवधारणाएँ : सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय (Basic Concepts: Meaning of Social Stratification)	1
2.	सामाजिक स्तरीकरण के आधार (Bases of Social Stratification)	15
3.	मार्क्सवादी नजरिया (Marxian)	31
4.	वेबरीयन (Weberian)	45
5.	प्रकार्यात्मक (Functionalist)	56
6.	विशेषताबोधक और अन्योन्य-क्रियात्मक (Interactional and Attributional)	68
7.	प्रजाति और नृजातीयता (Race and Ethnicity)	77

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
8.	जाति और वर्ग (Caste and Class)	88
9.	लैंगिक और असमानताएँ (Gender and Inequalities)	96
10.	गतिशीलता की संकल्पनाएँ एवं रूप (Concept and Forms of Mobility)	106
11.	सामाजिक गतिशीलता के घटक एवं शक्तियाँ..... (Factor and Forces of Mobility)	117
12.	सांस्कृतिक तथा सामाजिक पुनरुत्पादन (Cultural and Social Reproduction)	128



QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

सामाजिक स्तरीकरण
(Social Stratification)

B.S.O.E.-148

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. प्रस्थिति, सम्पत्ति तथा शक्ति के बीच अंतर बताइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'संयोजी सिद्धांत', अध्याय-2, पृष्ठ-15, 'सामाजिक स्तरण के आधार या आयाम'

प्रश्न 2. जाति के जनसांख्यिकीय आयाम पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'जाति का जनसंख्यात्मक विश्लेषण', पृष्ठ-9, प्रश्न 6

प्रश्न 3. व्याख्या कीजिए कि आयु, प्रजाति तथा लिंग सामाजिक स्तरीकरण के आधार कैसे हैं।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-16, 'आयु वर्ग-व्यवस्था', 'प्रजाति', पृष्ठ-17, 'लिंग'

प्रश्न 4. वर्ग पर मार्क्स की समझ की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-34, प्रश्न 2

प्रश्न 5. 'जीवन संभावना' से वेबर का क्या मतलब था? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-45, 'वर्ग और जीवन अवसर'

प्रश्न 6. गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? अंतरपीढ़ी तथा अंतरपीढ़ी गतिशीलता के बीच अंतर बताइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-10, पृष्ठ-106, 'परिचय', पृष्ठ-108, 'परिवर्तित पारस्परिक गतिशीलता और अंतःपारंपरिक गतिशीलता'

प्रश्न 7. पैरेटो के अभिजन वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत की चर्चा कीजिए।

उत्तर-पैरेटो के अनुसार समाज में दो वर्ग उच्च तथा निम्न वर्ग पाए जाते हैं। उच्च वर्ग के पास शक्ति होती है, जिसके बल पर प्रभुत्व जमाये रहते हैं। उच्च वर्ग में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिक्षित, बुद्धिमान तथा समर्थ होते हैं। समाज में इन्हीं लोगों का अधिक प्रभाव रहता है। अपने गुणों के बल पर ये उच्च लोग सामाजिक संतरण में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पैरेटो ने इसी वर्ग को अभिजात वर्ग कहा है।

पैरेटो ने अभिजात वर्गों को दो भागों में बाँटा है-

1. शासकीय अभिजात वर्ग-इस श्रेणी में वे अभिजात आते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रशासन संबंधी कार्यों में शामिल होते हैं।

2. अशासकीय अभिजात वर्ग-इस वर्ग में वे अभिजात आते हैं, जो शासन में तो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अन्य गुणों के आधार पर वे सम्मानित होती है, जैसे-वैज्ञानिक, कलाकार, शिक्षाशास्त्री, अर्थशास्त्री आदि।

पैरेटो के अनुसार इस अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर-नीचे आने-जाने का क्रम चलता रहता है। इस प्रक्रिया को ही पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत कहा है। अपने जीवन में प्राप्त सफलता अथवा असफलता के आधार पर निम्न वर्ग के व्यक्ति उच्च वर्ग में जा सकते हैं तथा उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में जा सकते हैं। प्रत्येक समाज में इस परिभ्रमण की गति एक समान नहीं होती है।

प्रत्येक समाज में परिभ्रमण की प्रक्रिया होती अवश्य है, क्योंकि कोई भी वर्ग पूर्णतया बन्द वर्ग नहीं हो सकता है। सचचाई यह है कि प्रत्येक समाज में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की प्रक्रिया तेज गति से ही चलती रहती है।

पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण को इस प्रकार स्पष्ट किया कि जो वर्ग सामाजिक संरचना में ऊपरी भाग में होती है, वह कालान्तर में भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने गुणों को त्याग कर निम्न वर्ग में आ जाते हैं। दूसरी ओर उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग में जो बुद्धिमान, कुशल, चरित्रवान तथा योग्य होते हैं, वे नीचे से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। इस प्रकार, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तथा निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इसी चक्रीय गति के कारण सामाजिक ढाँचा परिवर्तित हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के चक्र के प्रमुख तीन पक्ष हैं-राजनीतिक, आर्थिक तथा आदर्शात्मक। चक्रीय परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में उस समय गतिशील होता है, जब शासन सत्ता उस वर्ग के हाथ में आ जाती है, जिनमें समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक अधिक शक्तिशाली होते हैं।

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

सामाजिक स्तरीकरण
(Social Stratification)

B.S.O.E.-148

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. भारतीय समाज में वर्ग एवं जाति के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-89, 'जाति और वर्ग में गठजोड़'

प्रश्न 2. स्तरीकरण के अध्ययन में किंग्सले डेविस तथा विल्वर्ट मूरे के उपागम की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-57, 'डेविस और मूर का नजरिया'

प्रश्न 3. किशनगढ़ तथा राम नगला गाँवों में मैरिट के जाति सोपान की विवेचना की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-70, 'एम मैरियोट'

प्रश्न 4. वर्ग पर मार्क्स एवं वेबर के विचारों की तुलना एवं अन्तर बताइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-37, 'सामाजिक स्तरीकरण में वेबर के दृष्टिकोण'

प्रश्न 5. लैंगिक के सामाजिक निर्माण की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-98-99, 'समानता और असमानता : श्रम का लैंगिक विभाजन और सामाजिक लिंग सोच जन्य स्तरीकरण', 'सामाजिक लिंग सोच की सांस्कृतिक रचना', 'महिलाएं और घरेलू कामकाज', 'औद्योगीकरण और नगरीकरण का प्रभाव'

प्रश्न 6. जातीय अवधारणा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-78, 'नृजातीय की आरंभिक धारणा'

प्रश्न 7. जातीय गतिशीलता पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-जाति गतिशीलता का तात्पर्य जाति व्यवस्था की कठोर पदानुक्रमित संरचना के भीतर व्यक्तियों या समूहों के आंदोलन से है। जाति व्यवस्था भारत में एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है, जहां व्यक्ति विशिष्ट जातियों में पैदा होते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति, व्यवसाय और जीवन में अवसर निर्धारित करते हैं।

भारत में जाति व्यवस्था के प्रभाव-जाति व्यवस्था का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं-

1. सामाजिक असमानता-जाति व्यवस्था वंशानुगत जातिगत स्थिति के आधार पर समाज को स्तरीकृत करके सामाजिक असमानता को कायम रखती है। यह संसाधनों, अवसरों और सामाजिक गतिशीलता तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है।

2. भेदभाव और पूर्वाग्रह-जाति व्यवस्था निचली जातियों के विरुद्ध भेदभाव और पूर्वाग्रह को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हाशिए पर धकेला जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और बुनियादी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है।

3. व्यावसायिक सीमाएं-जाति-आधारित व्यावसायिक विभाजन व्यक्तियों की पसंद और अवसरों को सीमित कर देता है तथा उन्हें उनकी जाति से जुड़े विशिष्ट व्यवसायों तक सीमित कर देता है।

4. शैक्षिक असमानताएं-जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अवसरों में बाधा उत्पन्न की है, जिससे शैक्षिक असमानताएं बढ़ी हैं और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता सीमित हुई है।

5. अंतर-जातीय संघर्ष-जाति व्यवस्था अक्सर अंतर-जातीय संघर्षों और तनावों को जन्म देती है, जिससे सामाजिक सामंजस्य प्रभावित होता है और सामाजिक विभाजन पैदा होता है।

जाति गतिशीलता के प्रकार-जातिगत गतिशीलता अलग-अलग रूप ले सकती है, जिससे व्यक्ति या समूह जाति व्यवस्था की पदानुक्रमिक संरचना को पार कर सकते हैं। जातिगत गतिशीलता के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं-

1. ऊर्ध्वाधर गतिशीलता-ऊर्ध्वाधर गतिशीलता जाति व्यवस्था के सामाजिक पदानुक्रम के भीतर ऊपर या नीचे की ओर गति को संदर्भित करती है। इसमें किसी की जन्म जाति की तुलना में उच्च या निम्न जाति का दर्जा प्राप्त करना शामिल है।

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification)

प्रमुख अवधारणाएँ : सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय (Basic Concepts: Meaning of Social Stratification)



परिचय

सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से सामाजिक श्रेणियों और समाज के समूहों को एक-दूसरे से उच्च या निम्न श्रेणी में रखा जाता है। उनकी सापेक्षिक स्थिति को जानने के लिए ही उनकी कसौटी और विशेषाधिकारों को देखा जाता है। सामाजिक स्तरों से प्राप्त होने वाले नैसर्गिक गुणों व उनके द्वारा प्राप्त होने वाले गुणों को हम पृथक्-पृथक् श्रेणियों में रख सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण के रूप में काम करने वाले मानकीय सिद्धांतों को प्रदत्त और अर्जित पैमाने ही परिभाषित कर सकते हैं।

अध्याय का विहंगावलोकन

उद्वािकासीय प्रक्रिया

जब उत्पादन की प्रौद्योगिकियों में बुनियादी बदलाव आया तभी सामाजिक-स्तरीकरण का विकास एक संस्था के रूप में हुआ। पशुपालन और कृषि में आये बदलावों से जटिल प्रौद्योगिकी एवं सामुदायिक जीवन में स्थायित्व समाज के महत्वपूर्ण तत्व बन गये। इन अर्थव्यवस्थाओं ने ज्यादा उत्पादन के लिए पशु और अनाज के रूप में संपदा को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। जब खाद्य संसाधन सुनिश्चित होने लगे तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और पैदावार सामग्रियों और वस्तुओं के आदान-प्रदान में बढ़ोत्तरी होने लगी। समाज के जिस वर्ग का संपदा और सत्ता पर ज्यादा नियंत्रण था, उन वर्गों के लिए कालांतर में लेन-देन की युक्तियों का आविष्कार हुआ। जहाँ प्रौद्योगिकियाँ के विकास और श्रम विभाजन के साथ-साथ विशेषज्ञता प्राप्त समूहों का उदय हुआ, वहीं शहर और देहात में विभाजन उत्पन्न हो गया। इसलिए सामाजिक संरचना में आने वाली जटिलताओं को नियंत्रण करने

के लिए विस्तृत संस्थानों की आवश्यकता होने लगी। जैसे-शासक वर्ग, धर्म की संस्थागत स्वरूप आदि। उद्वािकासीय संबंधी कार्यों के कारण ही सामाजिक स्तरीकरण संस्था का उदय हुआ।

संयोजी सिद्धांत

स्थिति, संपदा और सत्ता सामाजिक सिद्धांत के तीन मुख्य संयोजी सिद्धांत हैं। उद्वािकासीय प्रक्रिया में इन तीनों सिद्धांतों का मुख्य स्थान है। ऐसे समाजों में जिनमें सामाजिक स्तरीकरण की संस्था नहीं थी, जैसे भोजन संग्रह करने वाले और शिकारी समुदाय, इनमें से कुछ व्यक्तियों को नायक समझा जाता था। इन समुदायों में आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण योग्यता रखने वाले लोगों को उच्च योग्यता प्रदान की जाती थी और इसी कारण से सामाजिक विभेदन अर्थात् समाज में रहने वाले व्यक्तियों में विभेद का जन्म होने लगा। जब लोगों के समूहों को सामाजिक श्रेणी के आधार पर बाँटा जाने लगा तब सामाजिक स्तरीकरण का विकास हुआ।

सामाजिक प्रस्थिति

सामाजिक प्रस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है। लोगों के समूहों का विभाजन समाज में उनकी प्रतिष्ठा और आदर के आधार पर करना ही सामाजिक प्रस्थिति है। प्रतिष्ठा को एक गुणात्मक विशेषता माना जाता है। जो गुण जन्म से ही विरासत में प्राप्त होता है, उसे प्रदत्त गुण कहा जाता है। इस गुण को हम अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक-प्रस्थिति सिद्धांत को प्रदत्त का सिद्धांत भी कहते हैं। भारतीय समाज में जाति इसका उदाहरण है।

संपदा

संपदा सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा संयोजी सिद्धांत है। जब प्रौद्योगिकी में उन्नति और उत्पादन की रीति में बदलाव आता है,

तभी समाज में संपदा उत्पन्न होती है, जैसे-आखेट और भोजन संग्रहण अर्थव्यवस्था से व्यवस्थित कृषि में बदलाव। इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही सामाजिक स्तरीकरण का जन्म हुआ और साथ में ही संयोजी सिद्धांतों में काफी बदलाव आया। आर्थिक उन्नति से समाज में ज्यादा संपदा पैदा हुई, जिससे संपदा के चिन्हकों का संचय हुआ। जैसे-पशुधन, अनाज खनिज पदार्थ आदि। इस स्थिति में आकर दो वर्ग बन गए-पहला संपन्न और दूसरा विपन्न।

सत्ता

सत्ता को सामाजिक स्तरीकरण का तीसरा संयोजी सिद्धांत कहा जाता है। समाज में सामाजिक स्थिति और संपदा को श्रेणी-निर्धारण में आधार समूह विशेषताओं से स्पष्ट रूप से जोड़ा जा सकता है। सत्ता का सिद्धांत सामाजिक प्रस्थिति और संपदा से पृथक है। यह एक बिखरा हुआ गुण है, क्योंकि समाज में जिन समूहों के पास संपदा का अधिक संचय होता है, वही इस गुण को अपनाता है, अर्थात् सत्ता का प्रयोग करता है। सत्ताधिकार की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि समाज में उच्च स्थिति प्राप्त वर्ग अन्य लोगों पर बल प्रयोग करके अपनी इच्छा थोपना चाहता है।

भारत में जाति और वर्ग

जिस प्रकार सत्ता, संपदा और सामाजिक-प्रस्थिति सामाजिक स्तरीकरण की नींव रखते हैं, उसी प्रकार जाति और वर्ग भी सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हैं। जाति और वर्ग के अभाव में समाज की संरचना संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक स्थिति समूह का मुख्य उदाहरण जाति को माना जाता है। वर्ग उस सिद्धांत पर आधारित है, जो समाज संपदा संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। जाति सामाजिक स्थिति के क्रम में श्रेणीबद्ध विशिष्ट जाति समूहों का संबोधन है। लगभग सभी धार्मिक समूह अलग-अलग समुदायों में विभक्त हैं, जिनमें जाति विशेषताएँ हैं। जातियाँ स्थानीय, क्षेत्रीय और स्थानीय आदि चिन्हक को धारण किए रहती हैं। जातियाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग और परस्पर निर्भरता के आधार पर काम करती थी और गाँव और शहर दोनों में उनकी अपनी पंचायतें थीं। गाँव और शहर में अपने केंद्र थे। शहरी संघों के पास अपने संगठनों का एक नेटवर्क था।

समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी थे, जिनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी और उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने परिश्रम से ही कमाना पड़ता था। मार्क्स ने इन वर्ग के लोगों को सर्वहारा नाम दिया।

जाति और सामाजिक स्तरीकरण

जाति स्तरीकरण के आधार पर ही प्राचीन भारतीय समाज की संरचना आधारित थी। सामाजिक स्तरीकरण के तहत जीवन के सभी पहलुओं यथा-अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि के मुख्य सिद्धांत के रूप में जाति काम करती थी। भारतीय समाज को चार वर्गों में बाँटा गया था। लेकिन कालांतर में पाँचवाँ वर्ग बना, जिनमें उन वर्गों को शामिल किया गया था, जिन्हें समाज

ने नियमों के उल्लंघन के कारण उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया था। यह किसी वर्ग पर थोपा गया, उग्र किस्म का भेदभाव था। वर्ण व्यवस्था की अंतर्विवाह, पुश्तैनी पेशा, जन्मजात सदस्यता आदि विशेषताएँ मानी जाती हैं।

जाति का जनसंख्यात्मक विश्लेषण

भारत में जाति या वर्ण की जनसंख्याकीय हजारों वर्षों से काफी पृथक् रही है। एक जाति को 20 मील से लेकर 200 मील की परिधि में एक सामाजिक समूह के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता है, वरन् इसको एक वर्ण मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था को समाजशास्त्रीय संदर्भ का आधार माना जाता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय समूहों के रूप में जातियाँ हजारों की संख्या में मौजूद रही हैं। भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि भारत में 4,635 जाति जैसे समूह विद्यमान हैं। इस सर्वेक्षण से यह भी विदित हुआ है कि जो भी धार्मिक समूह हैं, वे सभी पृथक्-पृथक् वर्गों में विभाजित हैं, जिसमें जाति-विशेषताएँ हैं। गाँव और शहर दोनों ही क्षेत्रों में जाति लेन-देन की व्यवस्था को लेकर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस प्रकार के वर्ग के लोग आपसी सहयोग से काम करते हैं। गाँव और शहर दोनों ही क्षेत्रों की अपनी-अपनी पंचायतें होती थीं। दोनों ही क्षेत्रों के पास अपना-अपना नेटवर्क भी होता था और यदि किसी भी लेन-देन में आपसी विवाद होता था, तो उसे पंचायत के पास ले जाया जाता था।

कृषि-व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबे समय से सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत वर्ण के स्थायित्व का आधार रहा। अधिक मृत्यु दर के कारण जनसंख्या भी स्थिर रहते हुए लगभग एक करोड़ के आस-पास बनी रही। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् ही स्थिर जनसंख्या का दौर टूटा, क्योंकि उसके पश्चात् महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु-दर को उन्नत चिकित्सीय सुविधाओं के कारण नियंत्रित करना संभव हो पाया था। भारत की जनसंख्या 1931 से बढ़ती गई। भारत को ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति ने एक पराश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया, जिससे विनिर्माण अर्थव्यवस्था और व्यापार की नींव डगमगाने लगी।

इसके कारण जहाँ नव औद्योगिककरण और विनगरीकरण हुआ वहीं गाँव के लोगों का भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। इसके कारण जो गाँव और शहरों के बीच लेन-देन का क्रम था, वह टूट गया। अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी फूट पड़ने लगी। धर्म और आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उन लोगों ने जाति भेद पर भी दबाव डालना आरंभ कर दिया। एक ही समूह को दो वर्गों में विभक्त कर दिया। प्रथम-उच्च श्रेणी, दूसरी-निम्न श्रेणी। इस भेदभाव से आपसी झगड़े होने लगे।

सामाजिक गतिशीलता

वर्ण व्यवस्था के स्तरीकरण में परिवर्तन लाने के लिए ही सामाजिक गतिशीलता को जन्म दिया गया। सामाजिक गतिशीलता

के द्वारा राज्यों की नीतियों को सीधे-सीधे जोड़ा गया, ताकि अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके। आजादी के पश्चात् भी इस प्रक्रिया में बढ़ोत्तरी होती गयी। यह प्रक्रिया अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और साथ ही भारत में जाति, धर्म या जातीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थी। स्वतंत्रता के पश्चात् जिस संविधान को स्वीकार किया गया था, वह भारत में सभी नागरिकों की स्थिति को समान मानता है। इसी कारण से गाँव और शहरों में जातिगत भेदभाव को अमान्य माना जाने लगा। आरक्षण की नीति भारत की सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को दर्शाती है। लोकतांत्रिक रोजगार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस नीति के सहायक तत्व हैं।

क्रम परंपरा के सिद्धांत

सामाजिक-स्तरीकरण में क्रम परंपरा के सिद्धांत को जाति के माध्यम से प्रतिबिंबित किया जाता है। फ्रांस के सामाजिक नृविज्ञानी लुई-ड्यूमोंट पाश्चात्य सामाजिक संरचना को भारतीय सामाजिक संरचना से एकदम विपरीत पाते हैं, क्योंकि जाति की यह संस्था संरचनात्मक दृष्टि से क्रम-परंपरा के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है।

ड्यूमोंट सामाजिक व्यवस्था की विशेषता के रूप में क्रम-परंपरा को परिभाषित करते हैं, जिनमें मानकीय सिद्धांत समाज के उपयोगितावादी सिद्धांतों को संचालित करते हैं। क्रम-परंपरा के अंतर्गत समाज के आदर्श मानकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य कारक निर्धारित नहीं कर सकते। वरन् इन्हें तय करने वाले कारक पृथक होते हैं, इसलिए ड्यूमोंट कहते हैं कि इनका ताना-बाना एकदम ही भिन्न होता है। उसमें वर्ण व्यवस्था में प्रचलित शुद्धि-अशुद्धि की अवधारणाओं को हम पाश्चात्य जगत के धर्म-निरपेक्ष मानकों की कसौटी पर नहीं कस सकते हैं।

क्रम-परंपरा के रूप में ड्यूमोंट की जाति व्याख्या पर समस्त विश्व में बहस छिड़ गयी। जातियों में स्तरीकरण और उसके स्थायीकरण में आर्थिक और राजनीतिक कारकों की भूमिका की अनदेखी के लिए उनकी आलोचना भी हुई।

भारतीय-समाज का ढांचा

भारत के सामाजिक ढांचे में उसकी वर्गीय संरचना प्रक्रियाओं का काफी गहन और विस्तृत वर्णन किया गया है। नृविज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने इस अध्ययन में काफी योगदान दिया है। भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करने के लिए भी काफी अध्ययन किया गया है।

स्थिति का सार

जाति में एक विशेष लक्षण होता है जिसे स्थिति का सार सिद्धांत कहा जाता है। आनुष्ठानिक क्रम-परंपरानुसार यदि किसी जाति की स्थिति निम्न होती है, तो उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति भी निम्न होती है। जाति एक संवृत्त समूह है

जिसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम सामाजिक या आर्थिक गतिशीलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जाति को विवृत समूह भी कहा जाता है। इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सदस्यता के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जाति एक समुदाय भी है, जिसकी गतिशीलता सामूहिक होती है, अर्थात् जिस कार्य को करना है, उसमें सभी सदस्यों की स्वीकार्यता अनिवार्य होती है। इसलिए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संपूर्ण समूह शामिल रहता है। जहाँ जाति में सामुदायिकतावादी विशेषता होती है, वहीं पर वर्ग में यह विशेषता नहीं होती है। वर्ग एक हित समूह होता है, जबकि जाति एक समुदाय है। वर्ग मिलकर चलने पर सामूहिक-सहचारिता को विकसित कर सकता है। नये सामाजिक और आर्थिक विकास और जातिगत सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के सजग होने से जाति समूह हित समूहों में तब्दील हो गए हैं।

ग्रामीण और शहरी समाजों में वर्गीय ढांचा एक-दूसरे से पृथक होते हैं। सामाजिक नृविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण वर्गीय संरचना में तीन वर्ग बनाए हैं—जमींदार, किसान और मजदूर वर्ग। गाँव में कुछ जातियाँ ऐसी भी होती हैं, जोकि छोटी संख्या में आर्थिक हित-समूह के रूप में विद्यमान रहती हैं, जैसे—दस्तकार, अहलकार आदि। कैथलीन गोग के अनुसार, ग्रामीण ढांचे को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है—बुर्जुवा वर्ग, छोटा बुर्जुवा वर्ग और श्रमिक वर्ग।

माक्सवादी विधि और धारणाएं

अर्थशास्त्रियों में भारत के वर्गीय ढाँचे के अध्ययन-विश्लेषण के लिए माक्सवादी विधि और धारणाओं के प्रयोग का चलन रहा है। समाजशास्त्रियों ने भी कालांतर में इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। भौतिक विभाजन के कारण ही वर्गों का निर्माण होता है। शारीरिक लक्षण, बौद्धिक विशेषताएं, धर्म, जाति या संप्रदाय आदि को माक्स वर्ग-निर्धारण का आधार नहीं मानता है। उसके वर्ग आर्थिक वर्ग हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर विकसित होते हैं। गाँव की कृषि अर्थव्यवस्था का रूप पूँजीवाद ने लिया। उत्पादन में बैंक ऋण और सहकारिता की भूमिका काफी बढ़ गयी है। अब नगदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्त्व मिल रहा है।

शहरी क्षेत्रों का वर्गीय ढाँचा भी बनियों और व्यापारियों, अर्द्ध कुशल कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों आदि में बाँटा रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात् ही व्यवसाय करने वाले वर्गों में बढ़ोत्तरी हुई है। नई प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण ही भारत की वर्गीय संरचना में बदलाव आ रहा है। इसी कारण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की संरचना में काफी विस्तार आया है, जैसे—हरित क्रांति के द्वारा एक मजबूत ग्रामीण मध्यम वर्ग का निर्माण किया गया था और कृषक जातियों के द्वारा ही हरित क्रांति का आरंभ किया गया था। इसके कारण ही कस्बों और शहरों में मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार बढ़ोत्तरी होती रही तो मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी।

सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था

अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से भारतीय समाज का वर्गीय ढांचा अब औद्योगिक और विशेषकर सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह हमारे जाति और वर्गीय ढांचे को जोड़ने के लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। नई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के साथ ही विभिन्न प्रदेशों और समुदायों के बीच पलायन के साथ-साथ नगरीकरण में तेजी आ सकती है, वर्ग और जातीयता को जाति-समूहों से अधिक महत्व तभी मिल सकता है जब राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को सामाजिक ढांचे में नये सिद्धांतों के साथ ही स्थान प्राप्त हो।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. जाति और सामाजिक स्तरीकरण पर एक नोट लिखिए।

उत्तर—मुख्य रूप से परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना का आधार जातिगत स्तरीकरण को ही माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जाति की प्रमुख भूमिका होती है। वर्ण वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार जाति को माना जाता है। जाति समूहों को वर्णों के माध्यम से चार वर्गों में विभाजित किया गया है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कालांतर में पांचवां वर्ण भी निर्मित किया गया था, जिसके अंतर्गत उस जाति समूह को सम्मिलित किया गया था जिसे समाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। जन्म पर आधारित सदस्यता को आनुवांशिक पेशा करने वाले जाति समूहों से पृथक कर दिया गया था। यहाँ सभी धार्मिक समूह अलग-अलग समुदायों में बंटे हुए हैं, जिनमें जाति-विशेषताएँ हैं, जो समूह जिस धर्म को मानता है वह दूसरे धर्म को मानने वाले समूह में सम्मिलित नहीं हो सकता है। जातियाँ स्थानीय, क्षेत्रीय या सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, स्थानीय इतिहास का पौराणिक कथाओं पर आधारित चिन्हक भी धारण किए रहती हैं। जातियों की स्थिति निम्न प्रकार की थीं—

1. वे गाँव और शहर दोनों जगह में लेन-देन की आर्थिक व्यवस्था के कारण बँधी रहती थी।
2. आपसी निर्भरता, सहयोग और वर्ण-व्यवस्था के आधार पर ही काम करती थी।
3. गाँव और शहर में अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी-अपनी पंचायतें थीं। इसके अलावा गाँवों व शहरों के बाहर भी इनका एक नेटवर्क था।
4. जब भी कभी अंतर्जातीय विवाद होता था, तो उनकी सुनवाई पंचायतों के समक्ष होती थी।

प्रश्न 2. नीचे दी गई सूची में कौन-सी अवधारणा शेष से मेल नहीं खाती?

- (i) हैसियत
- (ii) संपत्ति

(iii) सामंती

(iv) नगरीकरण

उत्तर—नगरीकरण।

प्रश्न 3. भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बारे में लिखिए।

उत्तर—पारंपरिक रूप से जाति में एक विशेष लक्षण होता है, जिसे स्थिति का सार सिद्धांत कहा जाता है। आनुष्ठानिक क्रम परंपरा में जाति की स्थिति निम्न होने पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति तक उस जाति की पहुँच भी उतनी ही छोटी होती है। जाति एक संवृत समूह है, जो कि जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। जिस जाति में जन्म लिया जाता है, वह उसी जाति का कहलाया जाता है। जाति को किसी आर्थिक या सामाजिक गतिशीलता के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जाति एक संवृत समूह है, जो प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग एक विवशत समूह है, जो प्राप्त होती है। इसकी सदस्यता उपलब्धि की कसौटी पर ही आधारित रहती है। जाति को एक अंतः विवाही समूह माना गया है, जिसकी अपनी उपसंस्कृति होती है। जहाँ जाति का आधार आर्थिक होता है, वहीं वर्ग का आधार सामाजिक संस्कृति को माना गया है। भारतीय सामाजिक संस्थानों में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी समाज में स्तरीकरण का आधार वर्ग को माना जाता है। वहीं भारत में इसका आधार जाति को माना जाता है। भारत को जातियों और संप्रदायों की परंपरा स्थली माना गया है। भारत में जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है, जो निम्न हैं—

1. एक ही जाति के सदस्य किसी और जाति में विवाह नहीं कर सकते हैं।
2. अधिकांश जातियों का कारोबार/रोजगार निश्चित होता है।
3. समस्त जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर ही आधारित होती है।
4. जातियों में ऊँच-नीच का एक संस्तरण पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य शिखर पर होती है।
5. प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान-पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। जाति व्यवस्था में विशेषताओं के साथ-साथ उनमें आने वाले परिवर्तनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कुछ कारक हैं, जो निम्न हैं—

1. संस्कृतिकरण—यह एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, जिनमें निम्न जाति के लोग ऊँची जातियों के व्यवहार प्रतिमान और जीवन पद्धति, संस्कृति का अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए उन लोगों को अपनी बुरी आदतों को त्यागना पड़ता है। संस्कृतिकरण के लिए एक जाति में कुछ नियमों को लागू किया जाता है, जैसे—